

‘देश को विकसित की कतार में खड़ा करना है तो तीन शिफ्ट में काम करें कर्मचारी’

इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर आलोचनाओं और चर्चाओं की बढ़ सी आ गई है

बैंगलुरु, 30 नवम्बर
इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर अपने सुझाव से बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने एक के बजाय तीन कामकाजी शिफ्टों की जरूरत पर जोर दिया। मूर्ति की ये टिप्पणी तब आई जब वह अगले 5–10 वर्षों में बेंगलुरु के विकास की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे थे।

29 नवंबर को आयोजित बेंगलुरु टेक समिट में जेरोधा के सह-संस्थापक निखिल काथ्य के साथ एक बातचीत के दौरान मूर्ति ने कहा, "इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेटी मैट्रो को पूरा करना और उन अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां बहुत सारी कंपनियां स्थित हैं।" इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचा उद्योग (इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री) से पारंपरिक एक-शिफ्ट से आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कस को सुबह 11 बजे आकर और शाम 5 बजे जाकर, सिर्फ

- नारायण मूर्ति ने कहा कि, कई विकसित देशों के लोग कम से कम दो शिफ्ट में काम करते हैं हमें अगर उन्हें विकास में पीछे छोड़ना है तो हमारी सरकार को इस ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है. देश में तीन शिफ्ट में काम करने का नियम लागू किया जाना चाहिये।**

- नारायण मूर्ति ने कहा कि, अगर भारत ने ऐसा किया तो यह बात तय है कि, हम बहुत जल्द जी.डी.पी. के मामले में चीन को पीछे छोड़ देंगे और पूरी दुनिया में हमारा वर्चस्व कायम हो जायेगा।**

एक शिफ्ट में काम नहीं करना चाहिए।”

रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी आकांक्षाओं वाले देशों में लोग अक्सर दोवक शिफ्टोंमें काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत भी इसी तरह का रुख अपनाए तो वह चीन की वृद्धि दर को पार कर सकता है। उन्होंने कहा, "देश में अन्य जगहों पर उच्च आकांक्षाओंवाले लोग काम करते हैं। मैंने दो शिफ्ट देखी हैं क्योंकि मैं आधी रात के आसपास लौटता था। और मैंने लोगों को ऐसे काम करते देखा है जैसे मानो वे

कल सुबह गायब हो जायेंगे। इसलिए, मैं वहां तीन शिफ्टों की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं दो शिफ्टों की गारंटी दे सकता हूँ।”

नारायण मूर्ति ने कहा, “अब अगर हम उन सभी देशों से बेहतर बनना चाहते हैं, तो हम यह क्यों नहीं कहते कि हमारे लोग तीन शिफ्ट में काम करेंगे? उनसे पूछें कि तीन शिफ्ट में काम करके अपना काम पूरा करने के लिए उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, और उन्हें वे चीजें प्रदान करें। मुझे लगता है कि इन्होंने से कुछ

चीजें हैं जो हमारे नेताओं द्वारा की जा सकती हैं। और अगर हमने ऐसा किया, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत अकेले विकास में ही नहीं, बल्कि चीन से भी तेजी से बढ़ सकता है। हमारा आधार ही है 3.5 ट्रिलियन, जबकि चीन का 19 ट्रिलियन है। लेकिन हम चीन से आगे निकल जायेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम चीन से आगे निकल जायेंगे। लेकिन इसके लिए त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है।”मूर्ति ने बातचीत के दौरान तीन चीजें बताईं कीं, जिनमें शहर के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए प्रतिभाशाली लोगों के वास्ते अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना और सरकार द्वारा त्वरित निर्णय लेना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बेंगलुरु का योगदान लगभग 35–37 है। उन्होंने कहा, "तो इसका मतलब यह है कि अगर आप भारत से कुल 200 बिलियन डॉलर के निर्यात को देखें तो आप सिर्फ बेंगलुरु से लगभग 75 बिलियन डॉलर की उम्मीद कर रहे हैं।”

सुरंग से निकले 40 श्रमिकों को एम्स से छुट्टी मिली

नैनीताल, 30 नवम्बर
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए श्रमिकों की एम्स में सघन स्वास्थ्य जांच कर ली गई है। 41 में से 40 श्रमिकों को एम्स प्रशासन ने क्लीयरेंस देकर डिस्चार्ज कर दिया है। जबकि एक श्रमिक की स्वास्थ्य जांच जारी है।

बृहस्पतिवार को एम्स ऋषिकेश के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. आरबी

- 41 में से 40 श्रमिकों को एम्स प्रशासन ने क्लीयरेंस देकर डिस्चार्ज कर दिया है। जबकि एक श्रमिक की स्वास्थ्य जांच जारी है।**

कालिया, जनरल मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रो. रविकांत व अस्पताल प्रशासन से डॉ. नरेंद्र कुमार ने बताया कि सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए सभी 41 श्रमिकों को बते बुधवार को एम्स में भर्ती किया गया था। प्रारंभिक जांच में किसी भी श्रमिक में चोट आदि जैसी कोई शिकायत नहीं पाई गई।

दूसरी तिमाही में देश की जी.डी.पी.

7.6 प्रतिशत रही

पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में देश की जी.डी.पी. 6.2 प्रतिशत रही थी

दूसरी तिमाही में यह 38.78 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.6 प्रतिशत अधिक है।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वर्तमानकीमत्त पर जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद 71.66 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जबकि 2022–23 की दूसरी तिमाही में यह 65.67 लाख करोड़ रुपये था, जो कि 2022–23 की दूसरी तिमाही की 17.2 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर की पहली छमाही में जीडीपी 82.11 लाख करोड़ रुपये रहा है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 76.22

देश में अब तक दस हजार जन औषधि केन्द्र खुले

नयी दिल्ली, 30 नवंबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जन औषधि केंद्रों का अधिकतम उपयोग करने का आग्रह करते गुरुवार को दस हजारजं जन औषधि केंद्र का देवघर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उद्घाटन किया। मोदी ने इस जन औषधि केंद्र की ऑनलाइन शुरुआत करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए जन औषधि केंद्र एक मील के पथर साबित हुए हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख

- प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र जनता को समर्पित किया।**

मांडविया मौके पर उपस्थित रहे। मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के माध्यम से जनता को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए एम्स, देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र जनता को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं बाजार दरों की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत सस्ती दरों पर बेची जा रही हैं।

अमेरिका के आरोपों की जांच के लिए समिति बनाई भारत ने, रिपोर्ट के आधार ही होगी कार्रवाई

अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के कथित प्रयास को लेकर अमेरिका के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया

नयी दिल्ली, 30 नवंबर (वार्ता)। भारत ने अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के कथित प्रयास को लेकर अमेरिका के बयानों को लेकर आजफिर कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बारे में विशेष ब्रीफिंग में अमेरिका एवं पन्नू को लेकर मुझे गये सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के दौरान, अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, बंदूकधारियों, आतंकवादियों और अन्य चरमपंथियों के बीच सांठगांठ से संबंधित कुछ इनपुट साझा किए हैं।

तेलंगाना में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार बहुत कम वोटिंग हुई

शाम पांच बजे तक 63.94 फीसदी ही वोटिंग हुई जबकि सन् 2018 में 73 फीसदी मतदान हुआ था

हैदराबाद, 30 नवंबर (वार्ता)। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में गुरुवार को कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा और राज्य के करीब 64 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने

मताधिकार का इस्तेमाल किया। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान के समापन के निर्धारित समय शाम पांच बजे तक कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं में से 63.94 प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने मतदान केंद्र पर पहुंचे। राज्य में कुल 119 निर्वाचन क्षेत्रों में से हालांकि 13 नक्सलवाद प्रभावित सीटों पर मतदान एक घंटा पहले (चार बजे) समाप्त हो गया था।

चुनाव अधिकारी ने मतदान के अंतिम आंकड़े बढ़ने की संभावना जतायी है। गौरतलब है कि 2018 में राज्य विधानसभा चुनाव में 73 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार मतदान प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव के

- राज्य में कुल 119 निर्वाचन क्षेत्रों में से 13 नक्सलवाद प्रभावित सीटों पर मतदान एक घंटा पहले (चार बजे) ही समाप्त हो गया था।**

- अंतिम मतदान प्रतिशत आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी लेकिन यह बात तय मानी जा रही है कि, अगर अंतिम आंकड़ों में पांच प्रतिशत और बढ़ोतरी हो जाती है तो भी कुल मतदान 69 प्रतिशत के करीब ही पहुँच पायेगा।**

तुलना में कम हुआ है। अंतिम मतदान प्रतिशत आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विकास राज ने कहा, 'विभिन्न स्थानों पर एक या दो छोटी-मोटी झड़पों को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा।

सीईओ राज ने बताया कि दो जगहों पर तकनीकी खराबी के कारण ईवीएम बदली गयीं। उन्होंने कहा कि उनके

कार्यालय को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के. कविता और अन्य राजनीतिक नेताओं के खिलाफ शिकायतें मिलीं, जिन्हें संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट मांगने के लिये भेजा गया था।

उन्होंने कहा, हमें सुश्री कविता के खिलाफ एक शिकायत मिली है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति याचिका खारिज

वाराणसी, 30 नवम्बर
ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को दस दिन का और समय मिल गया है। बार-बार समय मांगने पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया ने आपत्ति भी जताई और एएसआई की मांग खारिज करने की अपील की। लेकिन जिलाल जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। एएसआई को दस दिन का समय देने के साथ ही हिदायत भी दी और कहा कि अब एएसआई कोर्ट से कोई समय नहीं मांगेगा। अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट जमान करने के लिए अदालत से तीन सप्ताह का समय मांगा था। एएसआई की अर्जी पर बुधवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने तब आदेश सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली की राखी सिंह सहित पांच महिलाओं की ओर से शूगर गैरीट सहित अन्य विग्रहों के पूजा अधिकार की मांग

- वाराणसी की जिला अदालत ने आर्कियॉलजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विभाग को अपनी जांच पूरी करने के लिए 10 दिन की और मोहलत दी।**

वाली अर्जी पर सुनवाई के तहत जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था। जिला जज की अदालत ने एएसआई को सर्वे कर सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करने का आदेश एएसआई को दिया है। पहले यह रिपोर्ट अक्टूबर में ही जमा करनी थी। लेकिन बारिश और अन्य कारणों का हवाला देते हुए एएसआई लगातार रिपोर्ट जमा करने के लिए समय मांगता रहा।

मंगलवार को भी एएसआई की ओर से अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने

क्यों होता है एग्जिट...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
को आ रहे हैं, के एग्जिट पोलस के आंकड़े भ्रमित करने वाले हैं। इस बार अन्य को 5 से लेकर 21 तक सीटें दी जा रही है। इस बार भी यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अन्य आधिकार कितनी संख्या पर आकर ठहरेंगे। दरअसल इस बार राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा आरएलपी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन करीब एक दर्जन सीटों पर बड़ा मजबूत नजर आ रहा है। तीन सीटों पर कम्यूनिस्ट पार्टीयों मजबूत दिख रही है। करीब सात सीटों पर बसपा की मजबूत उपस्थिति दिख रही है। भारत ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी दोनों वागडू की 6 सीटों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती दिख रही हैं और करीब 9 से 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्यक्षी प्रमुख दलों के साथ मुकाबले में बने हुए हैं। अब इनमें से यदि आधे भी जीतकर आते हैं, तो एग्जिट पोल और परिणाम का आंकड़ा बिकुल पलट जाएगा।

वैसे भी राजस्थान में सिर्फ हर जिले की ही स्थिति अलग नहीं होती, बल्कि

हरेक जिले की हरेक सीट का समीकरण भी जातिगत हिसाब से अलग-अलग होता है। यही कारण है कि राजस्थान परिणाम का पहले से आकलन किया जाना बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उनके कारण दो दिन तक तो चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा।

एग्जिट पोल:...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
थी, पर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, में इस बार कांग्रेस की स्थिति जटिल है। तीन में से एक एग्जिट पोल ही कांग्रेस को बहुत दे रहा है। बाकी सब भाजपा की बढ़त दिखा रहे हैं।

भाजपा के लिए जन की बात ने 100–123 सीटें, रिपब्लिक टीवी-मैट्रिज ने 118–130 सीटें, टीवी 9 भारत वर्ष-पोल स्टूडेंट ने 106 से 116 सीटें दी है सिर्फ दैनिक भास्कर ने ही कांग्रेस को 118 से 130 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। इससे भाजपा को 95 से 105 सीटें दी है।

तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन, कांग्रेस को 6 5 और...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
अन्य सर्वेक्षणों में कांग्रेस को सहज रूप से आगे बताया गया है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए 62 से 72 सीटों की भविष्यवाणी करने वाले "पीपल्स पल्स" ने तेलंगाना में कांग्रेस को आगे बताया है, जबकि एक अन्य सफलमत चुनाव सर्वेक्षण कम्पनी "चाणक्य" का अनुमान है कि कांग्रेस को 67 से 78 सीटें मिलेंगी। एक अन्य सर्वेक्षण कांग्रेस को 72 सीटें दे रहा है। पोलिंग एजेंसी सी.पी.ए.सी. ने बी.आर.एस. को सिर्फ 41 सीटें दीं और कांग्रेस को 65 सीटों के साथ उससे काफी आगे बताया।

यह उन विभिन्न पोलिंग एजेंसियों के अनुमान हैं जिन्होंने मतदान बूथों पर वोट देकर बाहर आये लोगों से बातचीत की थी।

लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार तेलंगाना में कांग्रेस की हार्द सरकार बनेगी।

गुरुवार सायं, जैसे ही वोटिंग प्रक्रिया पूर्ण हुई कांग्रेस खेमा उत्साहित हो गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस प्रमुख रेवन्त रेड्डी ने पार्टी के कई नेताओं के साथ एक भीड़ भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को

संबोधित किया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। संकेत हैं कि रेड्डी राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। रेवन्त रेड्डी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 9 दिसम्बर, पानी यानी कि सोलिया गांधी के जन्मदिन पर शपथ ली जाएगी। वास्तव में वह सतर्क एवं राजनीतिक समझबूझ वाले हैं, तभी तो उनका यह कहना है कि मुख्यमंत्री पद संभालने वाले के बारे में कांग्रेस का केन्द्रीय नेतृत्व पार्टी के निर्वाचित विधायकों से सलाह-मशविरा करने के बाद ही कोई निर्णय लेगा।

वह स्वयं के लिए कहते हैं कि तेलंगाना में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनकर वह पहले ही एक बड़ा पद प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी वह स्पष्ट रूप से आगे हैं।

जरा गौर कीजिए कि उन्होंने पिछले ढाई साल में पार्टी के लिए क्या किया। वर्ष 2018 में हुए तेलंगाना विधानसभा के पिछले चुनाव में कांग्रेस कुल 119 सीटों में से 19 ही जीत सकी थी, लेकिन पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद रेवन्त रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस को नए

सिरे से खड़ा करना शुरू किया। उन्होंने कई नेताओं की घर वापसी करवायी, कई असंतुष्ट मुख्यमंत्री हो सकते हैं। रेवन्त रेड्डी पहले ही घोषणा व अन्य पार्टियों के मजबूत नेताओं को कि कांग्रेस के साथ जोड़कर यहाँ अपनी पार्टी को सशक्त कर दिया।

वास्तव में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मीडिया तक में ना तो अधिक देखा अथवा महसूस किया जा रहा था और जब भाजपा तेलंगाना में सबसे तेजी से उभरती हुई पार्टी के रूप में सामने आई और उसने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ से चार सांसदों को जितकर और प्रेटर हैदराबाद के जी.एस.एम.सी. महानगर पालिका चुनावों में द्वितीय स्थान पर रहकर अपना दमखम दिखाया था तब लोग कांग्रेस की हंसी उड़ाया करते थे।

अत: रेवन्त रेड्डी की उपलब्धि यह है कि उन्होंने राज्य में कड़ी मेहनत कर भाजपा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। वास्तव में, स्वयं रेड्डी और कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की भारत सदी थी, लेकिन पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद रेवन्त रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस को नए

राज्य में रेवन्त रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने शनै: शनै: किन्तु निश्चित रूप से उस जनता में गहरी जड़ें जमाना शुरू किया जो सत्तारूढ़ बी.आर.एस. और मुख्यमंत्री के.सी.आर. के कथित भ्रष्टाचार और कुशासन से पीड़ित होकर बदलाव चाह रही थी। कांग्रेस ने अपना सबसे अच्छा चुनाव प्रचार अभियान चलाकर सटीक प्रहार किए और जनता का विश्वास जीता। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा पिछड़ों, एस.सी., एस.टी. दलितों, मुस्लिमों और ईसाईयों को कांग्रेस में लौटना। उनमें से अधिकांश बी.आर.एस. के साथ थे। कांग्रेस यह उपलब्धि हासिल करने में समर्थ रही है या नहीं, इसका पता मतगणना वाले दिन, 3 दिसम्बर को चल जाएगा। अब यह देkhना है कि एग्जिट पोल के परिणाम क्या वास्तविक चुनाव परिणामों क रूप में सामने आते हैं?

इस बीच, बी.आर.एस. नेता एवं मंत्री के.टी. रामारव ने एग्जिट पोल्स को "बकवास एवं हास्यापद" बताते हुए खारिज कर दिया, लेकिन इसके साथ ही उनकी यह शिकायत भी थी कि साने 5:30 बजे ही एग्जिट पोल्स से

अनुमतिगत क्यों दे दी गई। लेकिन चुंकि वह अपने पार्टी का डर और कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करना चाहते, खासतौर पर सार्वजनिक रूप से तो नहीं, इसलिए उन्होंने घोषणा की कि बी.आर.एस. रविवार को वापसी करेगी और फिर से अपनी सरकार बनाएगी।

दूसरी ओर रेवन्त रेड्डी ने कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता तथा कांग्रेस का समर्थन करने और राज्य में जड़ें जमाएँ बैठी बुराई को दूर करने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन करने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद अदा किया और वादा किया कि वह एक ऐसा तेलंगाना बनाएंगे जिसके लिए जनता ने संघर्ष किया था और कुर्बानियां दी थीं। कांग्रेस को यदि तेलंगाना में बहुमत हासिल नहीं भी होता है तब भी एग्जिट पोल के आंकड़ें कांग्रेस के कायापलट की कहानी बताते हैं। वह कई विधानसभा में सर्वाधिक विधायकों वाली या दूसरे नम्बर की पार्टी के रूप में उभरेगी, जो कि लेकिन इसके साथ ही उनकी यह शिकायत भी थी कि साने 5:30 बजे ही एग्जिट पोल्स से

दूसरी ओर रेवन्त रेड्डी ने कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता तथा कांग्रेस का समर्थन करने और राज्य में जड़ें जमाएँ बैठी बुराई को दूर करने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन करने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद अदा किया और वादा किया कि वह एक ऐसा तेलंगाना बनाएंगे जिसके लिए जनता ने संघर्ष किया था और कुर्बानियां दी थीं।

कांग्रेस को यदि तेलंगाना में बहुमत हासिल नहीं भी होता है तब भी एग्जिट पोल के आंकड़ें कांग्रेस के कायापलट की कहानी बताते हैं। वह कई विधानसभा में सर्वाधिक विधायकों वाली या दूसरे नम्बर की पार्टी के रूप में उभरेगी, जो कि लेकिन इसके साथ ही उनकी यह शिकायत भी थी कि साने 5:30 बजे ही एग्जिट पोल्स से

कांग्रेस को यदि तेलंगाना में बहुमत हासिल नहीं भी होता है तब भी एग्जिट पोल के आंकड़ें कांग्रेस के कायापलट की कहानी बताते हैं। वह कई विधानसभा में सर्वाधिक विधायकों वाली या दूसरे नम्बर की पार्टी के रूप में उभरेगी, जो कि लेकिन इसके साथ ही उनकी यह शिकायत भी थी कि साने 5:30 बजे ही एग्जिट पोल्स से

हमास ने...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि इजरायल और हमास के बीच चार दिवसीय मानवीय संघर्ष विराम, दो दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इजरायल ने विस्तार पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन मंगलवार को शुरुआत में कहा कि अगर अधिक इजरायली बंधकों को रिहा किया जाता है तो उसने 50 और महिला फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहाई की मंजूरी दे दी है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को अचानक किए गये हमले के दौरान हमास आतंकवादियों द्वारा 200 से अधिक बंधकों को गाजा ले जाया गया था, जिसने जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में घातक हवाई हमले और जमीनी हमले शुरू किये।

सोमवार से ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
किया गया एक महत्वपूर्ण विधेयक अन्य संसदीय बहस की प्रतीक्षा में है। एक अन्य विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें जे. एण्ड के. और पुडुच्चेरी में महिलाओं का कोटा बढ़ाने की बात है।

एक प्रस्तावित विधेयक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जिसे लोकसभा के पिछल सत्र में प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक निवर्तमान इण्डियन पीनल कोड 1860 का स्थान लेगा, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का उद्देश्य कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का स्थान लेना है।

^[1] राष्ट्रदूत, 30 नवंबर
इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर अपने सुझाव से बहस छेड़ दी है

^[2] बैंगलुरु, 30 नवम्बर
इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर अपने सुझाव से बहस छेड़ दी है

^[3] नयी दिल्ली, 30 नवंबर
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए श्रमिकों की एम्स में सघन स्वास्थ्य जांच कर ली गई है

^[4] नयी दिल्ली, 30 नवंबर
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए श्रमिकों की एम्स में सघन स्वास्थ्य जांच कर ली गई है

^[5] नयी दिल्ली, 30 नवंबर
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए श्रमिकों की एम्स में सघन स्वास्थ्य जांच कर ली गई है

^[6] नयी दिल्ली, 30 नवंबर
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए श्रमिकों की एम्स में सघन स्वास्थ्य जांच कर ली गई है

^[7] नयी दिल्ली, 30 नवंबर
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए श्रमिकों की एम्स में सघन स्वास्थ्य जांच कर ली गई है

^[8] राष्ट्रदूत, 30 नवम्बर
इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर अपने सुझाव से बहस छेड़ दी है

^[9] बैंगलुरु, 30 नवम्बर
इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर अपने सुझाव से बहस छेड़ दी है

^[10] नयी दिल्ली, 30 नवंबर
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए श्रमिकों की एम्स में सघन स्वास्थ्य जांच कर ली गई है

^[11] नयी दिल्ली, 30 नवंबर
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए श्रमिकों की एम्स में सघन स्वास्थ्य जांच कर ली गई है

^[12] नयी दिल्ली, 30 नवंबर
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए श्रमिकों की एम्स में सघन स्वास्थ्य जांच कर ली गई है

^[13] नयी दिल्ली, 30 नवंबर
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए श्रमिकों की एम्स में सघन स्वास्थ्य जांच कर ली गई है

^[14] नयी दिल्ली, 30 नवंबर
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए श्रमिकों की एम्स में सघन स्वास्थ्य जांच कर ली गई है